IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

जी–20 में भारत की भूमिका, लक्ष्य एवं परिणाम

डॉ. कुमुद भारद्वाज
असिस्टेन्ट प्रोफेसर
एस.सी.ई.आर.टी. दिल्ली

सारः– जी–20 एक अन्तः सरकारी मंच हैं जिसमें 14 सम्प्रभु राज्य, अफ्रीकी संघ व यूरोपीय संघ शामिल है। किसी भी देश राष्ट्र की उन्नति तब संभव है जब उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर काम किया जाए इसी के साथ–साथ उसमें अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, (क्लाईमेट चेंज) और सतत विकास जैसे मुद्दे शामिल होने से विश्व स्तर पर कोई न कोई हल निकलने की संभावना होती हैं इसी को ध्यान में रखते हुए व देश के लोगों के लिए रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से जी–20 जैसा मंच तैयार किया गया। जिसका असर देशों के प्रत्येक नागरिक पर पड़ेगा।

कुंजी शब्द :– जी–20, वैश्विक, शिखर सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रीय।

जी–20 क्या हैं :– जी–20 जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह 20 देशों का एक ऐसा समूह है जिसे 1999 में एशिया के आए आर्थिक संकट के कारण देशों के वित्त मंत्रियों और सैन्ट्रल बैंक के गर्वनरों ने मिलकर तैयार किया था। इसमें ग्लोबल अर्थव्यवस्था और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। वैसे तो इस समूह का जोर अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना रहा है लेकिन वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता रहा है, इसमें सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दे भी जुड़ते चले गए। साल 2007 में पूरी दुनिया पर आर्थिक मंदी का साया मंडरा रहा था ऐसे में जी–20 के स्तर को और ऊपर उठाकर यह राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर लाया गया जहाँ देश के राष्ट्र अध्यक्ष इसमें प्रतिभागी बनने लगे।

जी–20 का इतिहास :– जी–20 की स्थापना सितम्बर 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। 1997 के पहले एशियाई वित्तीय संकट के बाद दुनिया के कई देशों ने माना कि इन मुद्दों पर चर्चा की आवश्यकता है। प्रारम्भ में इसमें सिर्फ 7 देश–अमेरिका, कनाड़ा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली के विदेश मंत्री शामिल हुए थे।

जी–20 का कोई मुख्यालय नही हैं इसके तहत शिखर सम्मेलन का आयोजन सदस्य देशों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इसका संचालन बिना स्थायी कर्मचारियों के किया जाता है। अध्यक्ष बनने वाला देश पूरे वर्ष होने वाली बैठकों का आयोजन करता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियों लूला दा सिल्वा को जी–20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी है।

जी–20 में सम्मिलित देश :– जी–20 समूह में 19 देश अर्जेन्टीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाड़ा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किए, यूनाइटेड़ किंगडम और अमेरिका, इसके साथ ही इस समूह का 20वां सदस्य है यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के देशों का समूह। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष देश, कुछ देशों व संगठनों को मेहमान के तौर पर आमंत्रित करता है। जैसे भारत ने बांग्लादेश, मॉरीशिस, नीदरलैन्ड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर स्पेन और यूएई को बुलाया था।

जी–20 की ताकत बहुत ज्यादा है इसके सदस्य देशों के पास दुनिया की 85 फीसदी जी.डी.पी., 75 फीसदी ग्लोबल ट्रेड, दुनिया की 2/3 आबादी है, ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया फैसला दुनिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकता है।

जिस देश को जी–20 की अध्यक्षता मिलती हैं वह उस साल जी–20 की बैठकें आयोजित करवाता है वह बैठक का एजेन्डा पेश करता है। जी–20 दो सामानांतर कार्यों को करता है। एक वित्त पर जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री और सेन्ट्रल बैंक के गवर्नर मिलकर काम करते हैं, दूसरा शेरपा, जिसमें हर देश का एक शेरपा लीडर होता है शेरपा असल में उन्हें कहा जाता है जो पहाड़ों में किसी भी मिशन को आसान करने का काम करते हैं। जी–20 के शेरपा अपने–अपने देश के प्रमुख का काम आसान करने का जिम्मा उठाते हैं। सभी देशों के शेरपा बैठकों के जरिए अलग–अलग मुद्दों पर आपसी सहमति बनाने का कार्य करते हैं।

शिखर सम्मेलन के उद्देश्य :–

- वैश्विक आर्थिक वित्तीय मुद्दों को संबोधित करना।
- वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना।
- टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देना।
- वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना।
- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
- वैश्विक अर्थिक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।
- सदस्य देशों के बीच संवाद व सहयोग को बढ़ावा देना।
- अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर चर्चा और समन्वय स्थापित करना।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए प्रोत्साहन व वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों का समन्वय करना।

शिखर सम्मेलन से लाभ :– मजबूत समूह होने के कारण इस सम्मेलन के दौरान लिए गए फैसलों को मानने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती, यह आर्थिक रूप से ताकतवर देशों का समूह है इस कारण से यहाँ लिए गए फैसलों से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर काफी असर होता है। जब बैठक खत्म होती है तब एक साझा बयान जारी करके आप सहमति भी बनाई जाती है, जिसकी जिम्मेदारी अध्यक्ष के ऊपर होती है।

जी–20 के प्रमुख कार्य :–

(i) **आर्थिक नीति समन्वय :–** जी–20 सदस्य देशों के लिए आर्थिक नीतियों पर चर्चा और समन्वय करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

(ii) **वित्तीय स्थिरता :–** जी–20 बैंकिंग नियमों, सीमा पर वित्तीय प्रवाह और वित्तीय संस्थानों की निगरानी जैसे मुद्दों को संबोधित करके वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है।

– वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की निगरानी और सिफारिश करने के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना।

(iii) **व्यापार और निवेश :–** व्यापार और निवेश जी–20 के मुख्य कार्य में से है। इसमें सदस्य देश मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देकर बाधाओं को कम करने व निवेश को सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम करते हैं।

– यह शिखर सम्मेलन नेताओ को व्यापार विवादों को संबोधित करने और बहुपक्षीय व्यापार वार्ता को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करते हैं।

(iv) **विकास और समावेशिता :–** इसमें गरीबी, सतत विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे मुद्दों को सम्बोधित किया जाता है।

– अफ्रीकी देशों के निवेश के माहौल में सुधार करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

– यह बैठकों की एक श्रृंखला के माध्यम से संचालित होता है जिसमें वार्षिक शिखर सम्मेलन, वित्त मंत्रियों की बैठकें और समूह चर्चाएँ शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन शमन :–

- जी–20 ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े आर्थिक खतरों और बेहतर भविष्य की ओर होने वाले रास्तों पर भी जोर दिया है।
- जी–20 देशों ने प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए कुनमिंग–मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (जी.बी.एफ.एफ.) को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का भी वादा किया है।
- घोषणा पत्र में नेताओं ने सतत विकास के साथ जलवायु वित्त, स्वच्छ ऊर्जा, प्लास्टिक प्रदूषण, आपदाओं के जोखिम को कम करना, प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और बहाली की बात कही।

भारत की भूमिका:– भारत का दृष्टिकोण हरित विकास, जलवायु वित्त और पर्यावरण के लिए जीवन शैली को बढ़ावा देना था। भारत शुरू से ही जी–20 के सभी सम्मेलनों में प्रमुखता से शामिल रहा है। विश्व व्यापार संगठन में सुधार का मुद्दा भारत के लक्ष्यों में शामिल है भारत चाहता है कि

जी–20 केवल व्यापार का मुद्‌दा नहीं रहे। जी–20 देशों ने भारत के सतत और समावेशी विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों और वैश्विक अर्थव्यवस्था हेतु भारत के योगदान को अहम बताया है।

- वैश्विक अर्थव्यवस्था, टिकाऊ विकास, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अपराधियों पर कार्यवाही कुछ ऐसे मुद्‌दे हैं जिनसे पूरी दुनिया का हित जुड़ा है। भारत का मानना है कि इन मुद्‌दों पर सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ना चाहिए।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी ढाँचे को मजबूत बनाने पर बल दिया है, ताकि आतंकियों को हथियार की खरीद के लिए पहुँचाए जाने वाले पैसे पर रोक लगाई जा सके।
- 9–10 सितम्बर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुए जी–20 शिखर सम्मेलन केबिनेट ने 'एक पृथ्वी' 'एक परिवार' 'एक भविष्य' की थीम के विभिन्न पहलुओं को तय करने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विज़न Vision की सराहना की। जन भागीदारी वाले दृष्टिकोण ने जी–20 के कार्यक्रमों और गतिविधियों में हमारे समाज के व्यापक वर्गो को शामिल किया।
- यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत ने जी–20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजवानी की। इस शिखर सम्मेलन का विषय ''वसुधैव कुटुम्बकम'' था जिसका अर्थ है ''विश्व एक परिवार है।''
- जी–20 देशों की नई दिल्ली घोषणा में रूस यूक्रेन तनाव से लेकर धारणीय विकास, खाद्य सुरक्षा और वैश्विक जैव ईधन गठबंधन शुरू करने जैसे विविध वैश्विक मुद्‌दों पर सर्व सम्मत सहमति बनी।

जी–20 शिखर सम्मेलन 2023 की मुख्य विशेषताएँ–

(1) वर्ष 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करनाः–

यह जीवाश्म ईधन से स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

- वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देना वैश्विक चुनौतियाँ कमजोर समूहों विशेषकर महिलाओं और बच्चों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। इसलिए इसका लक्ष्य भुखमरी और कुपोषण का उन्मूलन करना है।
- घोषणा पत्र में मानवीय पीड़ा और यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा आपूर्ति श्रृंखला, मुद्रास्फीति तथा आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर उच्च स्तरीय सिद्धांतों के तहत सात सिद्धांतों के अन्तर्गत मानवीय

सहायता, खाद्य उत्पादन एवं खाद्य सुरक्षा नेट कार्यक्रम, जलवायु स्मार्ट दृष्टिकोण, कृषि खाद्य प्रणालियों की समावेशिता, एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण, कृषि क्षेत्र का डिजिटलीकरण, कृषि में जिम्मेदार सार्वजनिक व निजी निवेश को बढ़ाना शामिल है।

- जी–20 कृषि, खाद्य और उर्वरक में पारदर्शी, निष्पक्ष और नियम आधारित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
- नई दिल्ली घोषणा में स्पष्ट रूप से आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़े शब्दों में निंदा की है।

(2) स्वास्थ्य देखभाल में लचीलापन और अनुसंधान :–

- नई दिल्ली नेतृत्व कर्ताओं की घोषणा में स्वास्थ्य देखभाल पर काफी जोर दिया गया है और एक लचीली स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के निर्माण की आवश्यकता को प्राथमिकता दी गई है।
- लचीला न्यायसंगत, सतत समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के लिए वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने हेतु प्रतिबद्धता है और इसको संभव बनाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की केन्द्रीय भूमिका है।
- भारत की जी–20 अध्यक्षता ने आधुनिक चिकित्सा के साथ साक्ष्य आधारित पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के एकीकरण पर जोर दिया है।

(3) वित्त :–

- भारत की जी–20 अध्यक्षता ने क्रिप्टो मुद्रा (डिजिटल या वर्चुअल करेंसी) के लिए एक समन्वित व व्यापक नीति की नींव रखी।
- जी–20 देशों ने विश्व स्तर पर उच्च विकासात्मक माँगों को पूरा करने के लिए अधिक मजबूत और प्रभावी बहुपदीय विकास बैंकों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया।
- वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के इंडिया स्टैक मॉडल को एक आशाजनक दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार किया गया है।
- जी–20 देशों की नई दिल्ली घोषणा क्रिप्टो परिसंपत्ति परिस्थितिकी तंत्र के तेजी से विकास से जुड़े जोखिमों की निगरानी पर जोर देती है।

(4) भारत मकोंसुर तरजीही समझौता (Preferential Trade Agreement)

भारत और ब्राजील ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत मकोंसुर PTA के विस्तार हेतु मिलकर कार्य करने पर सहमति जताई है।

- मकोंसुर (एक व्यापारिक समूह जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, उरूग्वे, पैराग्वे) शामिल हैं व भारत PTA जून 2009 को प्रभाव में आया, इसका उद्देश्य उन चुनिंदा वस्तुओं पर सीमा शुल्क को खत्म करना है जिन पर भारत और मकोसुर ब्लॉक के बीच सहमति बनी थी।

(5) जलवायु वित्त पोषण प्रतिबद्धता :–

- इस वित्त पोषण में जलवायु वित्तपोषण में पर्याप्त वृद्धि पर जोर दिया गया है और बड़े बदलाव का आह्वान किया गया है।

(6) भारत का सांस्कृतिक प्रदर्शन :–

भारत मंडपम में यह अनुभव मंडपम से प्रेरित है।

- भगवान नटराज की कांस्य प्रतिमा यह चोल शैली की है।
- ओडिशा के सूर्य मंदिर का कोणार्क चल और नालंदा विश्वविद्यालय की छवि – यह प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के रूप में प्रयुक्त हुई है।
- तंजावुर पेंटिंग और तंजावुर एक शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली है।
- ढोकरा कला– यह कलाकृतियाँ पीतल की होती हैं और इनके टुकड़ों में कोई जोड़ नही होता है।
- बोधि वृक्ष के नीचे स्थापित भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति।
- विविध संगीत विरासत इसमें हिन्दुस्तानी, लोक संगीत, कर्नाटक, भक्ति से संबंधित प्रदर्शन शामिल था।

(7) भारत अमेरिका सहयोग :–

- भारत चीनी दूरसंचार उपकरणों के उपयोग को कम करने को प्रक्रिया के साथ अमेरिका के रिप एन्ड रिप्लेस पायलट प्रोजेक्ट का समर्थन करता है।
- भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष एवं कृत्रिम बुद्धिमता जैसे नए तथा उभरते क्षेत्रों को विस्तारित करने पर बल दिया।
- भारत अमेरिका ने प्रमुख रक्षा साझेदारी को मजबूत और विविधतापूर्ण बनाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- भारत ने अमेरिका के साथ GEF-414 जेट इंजन के निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस और हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के बीच वाणिज्यिक समझौते हेतु अधिसूचना प्रक्रिया पूरी की। यह समझौता भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में एक बड़ा कदम है।

जी–20 के शिखर सम्मेलन ने भारत को विश्व के लिए और विश्व को भारत के लिए तैयार करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। भारत ने अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया के प्रमुख देशों का प्रतिनिधित्व किया और उसे मौका मिला कि वह प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाने, सामूहिक कार्रवाई के लिए जोर डालने की अगुवाई करने और साथ ही विकासशील देशों के एजेंडो का चैंपियन बनने का अवसर मिला। भारत में आयोजित शिखर सम्मेलन 2023 में यह रजामंदी हुई कि एम.एस.एम.ई. आसानी से वैश्विक कारोबार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकेंगे और इस काम के लिए वैश्विक व्यापार एजेंसी के माध्यम से डाटा एक्सचेंज का गठन किया जाएगा। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के संबंधो को मजबूत करने के लिए यह शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण रहा है।

परिणाम :–

जी–20 शिखर सम्मेलन के परिणाम विश्व की वर्तमान स्थिति NAM नीति की प्रासंगिकता, भारत के लिए आगे की राह। दिल्ली में आयोजित जी–20 बैठक में भारत ने आश्चर्य जनक सफलता प्राप्त की और बाधाओं के बावजूद इस स्तर के आयोजन के अनुरूप एक सर्व सम्मत घोषणा प्रस्तुत करने में सफल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा एजेंडे में शामिल लगभग सौ मुद्दों पर सहमति का निर्माण कर सकना कोई मामूली उपलब्धि नहीं मानी जा सकती। कुल मिलाकर जी–20 शिखर सम्मेलन के प्राप्त परिणाम व्यापक वैश्विक समुदाय की आशाओं और इच्छाओं को प्रतिबिंबित करते प्रतीत होते है।

जी–20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा के सभी 85 अनुच्छेदो को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया, जिसमें चीन और रूस की सहमति के बावजूद उल्लेखनीय 100 प्रतिशत सर्वसम्मति प्राप्त हुई।

जी–20 की अब तक सबसे बड़ी उपलब्धि साल 2008 के आर्थिक संकट को मैनेज करता था। तब आर्थिक संकट को काबू करने में इस समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वही जी–20 ने आई.एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक में कुछ सार्थक बदलाव भी किए। जी–20 का गठन ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है इससे दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में तेजी से बदलाव हो रहा है।

- पहली बार विकास नीति का मुद्दा, शिखर सम्मेलन के एजेंडे में शामिल किया गया और तभी से डेवलपमेंट जी–20 के हर वार्षिक सम्मेलन का हिस्सा है।
- जी–20 नेताओं ने व्यापार के बहुपक्षीय दृष्टिकोण और व्यापार संगठन (डब्ल्यू टीओ) के सुधार के महत्व को पहचाना और नियम आधारित अंतराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ किया।
- जी–20 ने ऑनलाइन प्लेटफार्मो से आतंकवाद और आतंकवाद के लिए अनुकूल उग्रवाद को बढ़ावा नहीं देने और ऐसी सामग्री को अपलोड करने से रोकने पर बल दिया है।
- इसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया, वही नेताओं ने सदी के मध्य तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को नैट जीरों तक पहुँचाने का प्रण लिया।
- महामारी के बाद स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक समाधानों और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर चर्चा हुई।
- रूस यूक्रेन युद्ध भी चर्चा में शामिल रहा।

निष्कर्ष :– निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता हैं कि जी–20 शिखर सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ऊर्जावान किया है। इसके अतिरिक्त विकास करने के लिए संसाधनों की ज्यादा उपलब्धता, पर्यटन का विस्तार, वैश्विक कार्यस्थल में अवसर, मोटें अनाज के उत्पादन और खपत के जरिए मजबूत खाद्य सुरक्षां और जैव–ईंधन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता आदि महत्वपूर्ण परिणाम रहे। जो पूरे देश के लिए लाभप्रद रहेंगे। भारत की पहल के चलते अफ्रीकी संघ को जी–20 के स्थाई सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने समकालीन प्रोद्यौगिकी के मामले में भारत की प्रगति और साथ–साथ हमारी विरासत संस्कृति और परम्पराओं के प्रदर्शन का अवसर प्रदान किया भारत की युवा पीढ़ी ने शिखर सम्मेलन की गतिविधियों में जोर शोर से हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा समझौते और जैविक ईंधन गठबंधन का

सम्पन्न होना भी बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे। वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में उथल–पुथल के बीच सम्पन्न हुई जी–20 समूह की शिखर बैठक में निकले नतीजे भारत के लिहाज से सकारात्मक है। दुनिया के प्रतिदिन बदलते माहौल में आर्थिक विकास के लिए विकासशील देशों के बीच आपसी संवाद और तालमेल बेहद अहम है। ऐसे में तमाम देश आपसी सहयोग और समझदारी से खुद को भी आर्थिक सन्दर्भ तौर पर मजबूत कर सकते हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

- India Today 18 September 2023 www.indiatoday.in
- Yojana Nov 2023 e PPD India!@yojanajournal.
- प्रतियोगिता दर्पण जनवरी अंक 2023
- जी–20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम का सार https//www.zeeblz.com
- The Road map to Indian Presidency Pentagon Press ISBN 13 978-9390095742